

राजस्थान में नई सौर परियोजना

चर्चा में क्यों?

जैक्सन ग्रीन (भारत) और बलूलीफ एनर्जी (सगिापुर) ने राजस्थान में 1 गीगावाट के [सौर परियोजनाओं](#) के विकास के लिये साझेदारी की है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (3,400 करोड़ रुपये) का निवेश किया जाएगा।

मुख्य बंदि

- परियोजना का दायरा एवं समय-सीमा:
 - 1 गीगावाट पोर्टफोलियो में ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित तीन सौर परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - परियोजनाओं में [अंतरराज्यीय \(InSTS\) और अंतरराज्यीय \(ISTS\) ट्रांसमिशन प्रणाली](#) परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - [राजस्थान राज्य वदियुत उत्पादन नगिम लमिटिड \(RUVNL\)](#), [भारतीय सौर ऊर्जा नगिम लमिटिड \(SECI\)](#) और [राष्ट्रीय जलवदियुत नगिम लमिटिड \(NHPC\) लमिटिड](#) से बोली के माध्यम से 25-वर्षीय [वदियुत करय समझौते \(PPA\)](#) प्राप्त किये गए।
 - तीनों सौर परियोजनाओं के 2025-2026 के दौरान क्रमशः शुरू होने की संभावना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा वसितार लक्ष्य:
 - इस साझेदारी का लक्ष्य 2030 तक भारतीय ग्रिड में 5 गीगावाट से अधिक [नवीकरणीय ऊर्जा](#) जोड़ना है।
 - राजस्थान की परियोजनाएँ प्रतिवर्ष 1,800 GWh (गीगावाट घंटे) हरति ऊर्जा उत्पन्न करेंगी, जो 1.5 मिलियन घरों को वदियुत देने के लिये पर्याप्त होगी।
- पर्यावरणीय प्रभाव:
 - इस परियोजना से 25 वर्षों में 22 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।
 - यह सड़कों से 5 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है।
- रोज़गार सृजन एवं आर्थिक लाभ:
 - इस पहल से निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान रोज़गार सृजति होंगे।
- वत्ततीय एवं बैंकगि सहायता:
 - इस लेनदेन के लिये अर्नस्ट एंड यंग (EY) को निवेश बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया था।
 - जैक्सन ग्रीन सुरक्षित ऋण सुवधिएँ:
 - फर्स्ट अबू धाबी बैंक (मुंबई) से 2.96 बलियन रुपए।
 - HSBC (हांगकांग और शंघाई बैंकगि कॉरपोरेशन) से 600 मिलियन रुपए।
 - यह निधि घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय [EPC \(इंजीनियरगि, खरीद एवं निर्माण\)](#) परिचालनों को सहायता प्रदान करेगी।

वदियुत करय समझौता (PPA)

- ये वदियुत उत्पादकों और खरीददारों (आमतौर पर सार्वजनिक उपयोगिताओं) के बीच [दीर्घकालिक समझौते](#) (आमतौर पर 25 वर्ष) होते हैं।
- इसमें उत्पादकों को निश्चित दरों पर बजिली आपूर्ति करने के लिये प्रतिबद्ध करना शामिल है, जिससे महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षमता सुनिश्चित हो सके।
- वे अनुकूल नहीं होते और गतशील बाज़ार स्थितियों के अनुकूल ढलने में असमर्थ होते हैं।

इंजीनियरगि, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल

- इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- सरकार ने नज्जि कंपनियों से इंजीनियरगि ज्ञान के लिये बोलियाँ आमंत्रित की हैं।
- कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- नज्जि कषेत्र की भागीदारी न्यूनतम है और यह केवल इंजीनियरगि विशेषज्ञता के प्रावधान तक ही सीमित है।
- इस मॉडल की एक चुनौती यह है कि इससे सरकार पर भारी वत्ततीय बोझ पड़ता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-solar-project-in-rajasthan>

